(c) if so, the details of agreement and its likely impact on Indian food processing industry?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI K.P. SINGH DEO): (a) Under Indo-US Commercial Alliance, Indian and U.S. companies have expressed intent of greater collaboration with each other.

(b) Yes, Sir.

(c) While Government have not made any specific agreement with any foreign food company, the approvals for foreign investments that have been granted are within the policy framework of foreign investment of the country. These foreign investments are expected to bring in attendant benefits of technology, management, employment generation, market expansion and exports.

नई जहाजरानी और परिवहन नीति

232. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास नई जहाजरानी तथा परिवहन नीति शुरु करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो कब तक नई नीतियों की घोषणा किए जाने तथा लागू किए जाने की संभावना है; और

(ग) उक्त नीतियों की मुख्य बातें क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० राजशेखर मूर्ति): (क) से (ग) सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ द्वारा नौवहन नीति की रूपरेखा के संबंध में उठाए गए विभिन्न पहलुओं की जांच करने तथा अपनी सिफारिशें देने के लिए राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के तत्वावधान में सितम्बर, 1995 में एक समिति का गठन किया है। समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:—

(i) लाइनर, कन्टेनर, बहुविधि, शुष्क बल्क, आर्द्र बल्क, तटीय एवं अपतटीय आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय बेड़े के आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए किए जाने वाले उपाय,

(ii) अगले 5 से 10 वर्षों के लिए नियत किए जाने वाले टनभार लक्ष्य की प्रायोजना,

(iii) राष्ट्रीय बेड़े की कारगर तैनाती में मदद करने के लिए पत्तनों एवं जहाज-मरम्मत सुविधाओं जैसे अवसंरचना आधार को सुदृढ़ करने की आवश्यकता,

(iv) कार्गो आधार,

(v) मानव संसाधन विकास,

(vi) वित्तीय प्रोत्साहन,

(vii) कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

यह समिति अपनी रिपोर्ट 6 महीने के अन्दर प्रस्तुत करेगी।

राष्ट्रीय परिवहन समन्वय समिति के गठन पर योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

Recommendations of the Committee on deep sea fishing policy

233. SHRI GHUFRAN AZAM:
SHRI RAMDAS AGARWAL:

Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether the Murari Committee constituted by Government to look into the deep sea fishing policy has made recommendations for cancellation of existing deep sea fishing licences;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government propose to implement the recommendations of the committee in toto; and

(d) if so, by when and if not, the reasons therefor?